

महत्वपूर्ण

संख्या:826/2026-2063438/12-2099/55/2023

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०यू०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एफ०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि० (जैफेड), लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यूपीएसएस), लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विपणन सहकारी संघ (हॉफेड), लखनऊ।
6. स्टेट हेड, नैफेड, बखशी का तालाब, लखनऊ।
7. शाखा प्रबन्धक, एनसीसीएफ, शाखा - कानपुर नगर।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन जायद विपणन मौसम 2026-27 मूल्य समर्थन
योजनान्तर्गत फसल उरद, मूंग तथा मूंगफली (जायद) का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया अनु सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या:F.No.L-15016/62/2026-MPS(192762), दिनांक 18 जून, 2026 (छयाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें; जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी.एस.एस.) के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन जायद विपणन मौसम 2026-27 के लिए फसल उरद की अधिकतम मात्रा 97,970 मी० टन, फसल मूंग की अधिकतम मात्रा 48,298 मी० टन, तथा फसल मूंगफली की अधिकतम मात्रा 41,718 मी० टन का क्रय खरीद प्रारम्भ होने की तिथि से 90 दिन तक की अवधि तक किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:एस-354/नि०कृ०सां०/सूचना/पी०एस०एस०/जायद2025-26/लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उक्त फसलों की कुल संस्तुत अधिकतम मात्रा का क्रय केन्द्रीय नोडल क्रय एजेंसियों यथा नैफेड एवं एन.सी.सी.एफ. द्वारा 80:20 के अनुपात में निम्नवत् किया जाएगा:-

क्र० सं०	केन्द्रीय एजेंसी का नाम	फसल की मात्रा (मी० टन में)		
		उरद	मूंग	मूंगफली
1	नैफेड (कुल मात्रा का 80 प्रतिशत)	78,376.00	38,638.40	33,374.40
2	एनसीसीएफ (कुल मात्रा का 20 प्रतिशत)	19,594.00	9,659.60	8,343.60
कुल योग		97,970.00	48,298.00	41,718.00

साथ ही प्रदेश में कार्यरत राज्य सतरीय क्रय एजेंसियों द्वारा उक्त फसलों का क्रय 40:15:15:15 के अनुपात में निम्नवत् किया जाएगा:-

क्र० सं०	केन्द्रीय एजेंसी का नाम	फसल की मात्रा (मी० टन में)		
		उरद	मूंग	मूंगफली
1	यूपीपीसीयू (कुल मात्रा का 40 प्रतिशत)	39,188.00	19,319.20	16,687.20
2	यूपीपीसीएफ (कुल मात्रा का 15 प्रतिशत)	14,695.50	7,244.70	6,257.70
3	जैफेड (कुल मात्रा का 15 प्रतिशत)	14,695.50	7,244.70	6,257.70
4	यूपीएसएस (कुल मात्रा का 15 प्रतिशत)	14,695.50	7,244.70	6,257.70
5	हॉफेड (कुल मात्रा का 15 प्रतिशत)	14,695.50	7,244.70	6,257.70
कुल योग		97,970.00	48,298.00	41,718.00

- केन्द्रीय नोडल क्रय एजेंसियों को उपरोक्त फसलों के क्रय हेतु आवंटित किए गए जनपदों की सूची संलग्न है।
- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में फसल एवं भूमि के विवरण के सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS)/भूलेख पोर्टल का उपयोग करके फसल एवं भूमि विवरण का सत्यापन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त पोर्टलों पर किसान की भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं है वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उपलब्ध किसान विवरण का उपयोग सत्यापन के लिए किया जा सकता है, जो दोनों केन्द्रीय नोडल क्रय एजेंसियों के ई-समृद्धि/ई-सम्युक्ति पोर्टल के साथ पहले से ही एकीकृत है।

अतः पी.एस.एस. गाइड-लाइन्स तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या: L-15016/95/2020-MPS, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 यथासंशोधित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2025 एवं पत्र दिनांक 26 मई, 2026 (छायाप्रतियां संलग्न) द्वारा निर्गत निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, वास्तविक आगणित सरप्लस के आधार पर जिलावार क्रय केन्द्रों की संख्या तय करके, जिलाधिकारी के अनुमोदन से क्रय केन्द्र खोलकर प्रदेश में फसल मूंग, उरद तथा मूंगफली (जायद) का क्रय दिनांक 25 जून, 2026 से दिनांक 22 सितम्बर, 2026 तक (कुल 90 दिन) की अवधि में कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोक्त।

भववी
Digitally signed by
Sanjeev Ranjan
Date: 25-06-2026
(संजीव रंजन)
09:30:06
विशेष सचिव।

संख्या: 826(1)/2026-2063438/12-2099/55/2023, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ह०

(संजीव रंजन)
विशेष सचिव।

प्रदेश में ग्रीष्मकालीन जायद विपणन सत्र 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत फसल मूंग, उरद एवं मूंगफली (जायद) की खरीद हेतु केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित नैफेड एवं एनसीसीएफ के मध्य जनपद आवंटन की वास्तविक सूची:-

क्रमांक	नैफेड	एनसीसीएफ
1	बांदा	कानपुर नगर
2	चित्रकूट	मिर्जापुर
3	झांसी	आजमगढ़
4	महोबा	चन्दौली
5	हमीरपुर	मऊ
6	जालौन	आगरा
7	फतेहपुर	कन्नौज
8	कानपुर देहात	बस्ती
9	प्रयागराज	हरदोई
10	कौशाम्बी	एटा
11	ललितपुर	बहराईच
12	सोनभद्र	मथुरा
13	जौनपुर	महराजगंज
14	गाजीपुर	बरेली
15	औरैया	मेरठ
16	बलिया	पीलीभीत
17	सुल्तानपुर	सम्भल
18	रायबरेली	बागपत
19	प्रतापगढ़	अमरोहा
20	अमेठी	इटावा
21	वाराणसी	
22	उन्नाव	
23	अयोध्या	
24	मैनपुरी	
25	अम्बेडकर नगर	
26	लखनऊ	
27	फिरोजाबाद	
28	फर्रुखाबाद	
29	गोण्डा	
30	बाराबंकी	
31	संत रविदास नगर	

32	बलरामपुर	
33	संत कबीर नगर	
34	सीतापुर	
35	गोरखपुर	
36	कासगंज	
37	लखीमपुर खीरी	
38	देवरिया	
39	शाहजहांपुर	
40	बुलंदशहर	
41	श्रावस्ती	
42	रामपुर	
43	अलीगढ़	
44	हाथरस	
45	मुरादाबाद	
46	मुजफ्फरनगर	
47	कुशीनगर	
48	सिद्धार्थनगर	
49	गाजियाबाद	
50	सहारनपुर	
51	बदायूं	
52	शामली	
53	गौतमबुद्धनगर	
54	हापुड़	
55	बिजनौर	

45-180/12-2-2026

F. No. L-15016/62/2026-MPS (192762)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 18th June 2026

To,
The Managing Director,
NAFFED,
Sidhartha Enclave,
Ashram Chowk,
New Delhi

The Managing Director,
NCCF,
NCUI Complex, 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi-16

Subject: Implementation of Price Support Scheme (PSS) for procurement of Black Gram (Urad), Green Gram (Moong) and Groundnut during Summer 2026 season in Uttar Pradesh-reg.

Madam/Sir.

I am directed to refer to the Government of Uttar Pradesh's letter no.685/2026-1897141/12-2099/55/2023 dated 22.05.2026 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to convey the approval of this Department to implement the Price Support Scheme (PSS) for procurement of a quantity of 97,970 MT of Black Gram (Urad), 48,298 MT of Green Gram (Moong) and 41,718 MT of Groundnut during Summer 2026 season as per the PSS Guidelines, 2024.

2. The date of commencement of procurement shall be decided by the State Government and the procurement period shall remain 90 days from such date. Based on the decision of State Govt. the Central Nodal Agencies are requested to intimate the date of commencement of the procurement to this Department.
3. Before commencement of procurement, central nodal agency should verify the availability of scientific storage space, as per PSS Guidelines, arranged by the State Govt. within normal limit from the procurement centers. Procurement need to be limited only upto confirmed availability of scientific storage.
4. Central Nodal Agency should also ensure that the procurement is done through Aadhaar -based biometric/face authentication of registered farmers. Central Nodal agency shall dispose procured stock strictly as per provisions of prevailing PSS Guideline.
5. Central Nodal agency shall ensure the procurement of only FAQ stock from the registered farmers and proper storage thereof. Central Nodal Agencies and State Governments to ensure that procurement shall take place when the market price is below the Minimum Support Price(MSP).
6. State Govt. shall provide a revolving fund equivalent to at least 15% of the procurement cost of the sanctioned quantity and ensure that the payments are made directly in the bank account of farmers from whom procurement is made within 3 days of procurement. However, the reimbursement of the cost of providing such a revolving fund will be as per the PSS guideline. For making payment of procurement expenses against this sanction order, the central nodal agency, based on supporting documents, may withdraw funds from the cash credit account, which is backed by a Government Guarantee.

श्री अशोक
19/6/26

Ajit

7. Procurement operations from Kharif season 2025-26 should be in compliance of the instructions issued by this Department vide letter no. L-15016/95/2020-MPS dated 18.09.2025, updated on 11.11.2025 and dated 26.05.2026.

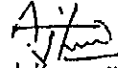
8. State Govt. is also requested to ensure exemption of Mandi taxes/cess that may be called by any name for the whole PSS operations in the State, including the direct procurement of pulses by CNAs and also support the establishment of direct procurement centres by CNAs.

9. Central Nodal Agencies and State Govt. are requested to capture the SC/ST beneficiary data under PSS to enable the utilisation of funds earmarked in the concerned head of PM-AASHA.

This issues with the approval of competent authority.

Encl.: As above.

Yours sincerely,



Ashutosh Kumar Jha
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 011-23388914
Email:ashutosh.jha@nic.in

Copy to:

1. Principal Secretary, Agriculture Department, Government of Uttar Pradesh, Krishi Bhawan, Madan Mohan Malviya Marg Lucknow - 226001
2. Joint Secretary (Pulses), DA&FW, Krishi Bhavan
3. Advisor, Costing Cell, DA&FW, Krishi Bhavan
4. Canara Bank, Large Cooperative Branch, Connaught Place, 2nd Floor, World Trade Tower, Barakhamba, New Delhi-110001.

No. L-15016/95/2020-MPS (E-91262)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Investment & Price Support Division

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated the 18th September, 2025

To

Chief Secretaries/ UT Administrators of all States/UTs

**Subject : Instructions regarding implementation of Price Support Scheme (PSS)
and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA.**

Madam/Sir,

Please refer to this Department's letter of even no. dated 29th October, 2024 and dated 20th March, 2025 regarding revised guidelines for implementation of Price Support Scheme (PSS), Price Deficit Payment Scheme (PDPS) and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA (Copies enclosed).

2. Apart from the provisions mentioned in the above schemes guidelines, the following instructions are issued for compliance while implementing PSS and MIS under PM-AASHA w.e.f. Kharif 2025-26 Season:

A. Price Support Scheme (PSS) :

- i. The registration of farmers must be done in a Portal devised for farmers registration by Central Nodal Agencies (CNAs) i.e. NAFED and NCCF.
- ii. The states where the registration of farmers is done on State's own Portal must ensure that all data is updated on real time basis and the CNAs should be able to fetch such data daily in their Portal through API integration without which the proposal under PSS will not be entertained.
- iii. Mandatory Use of Digital Crop Survey/integration into Agri-Stack: The States/UTs where Digital Crop Survey (DCS) / integration into Agri-Stack is being done, the CNAs /State Governments/UTs/State Level Agencies (SLAs)/Primary Level Agencies (PLAs) must use such data through API integration for auto-verification of farmer registration details. In case of failure of crop verification using automatically fetched DCS data, verification using traditional crop verification should be undertaken. In states where DCS is not carried out, the traditional crop verification must be adopted.
- iv. The farmer during registration can give name of three authorised persons along with their Aadhaar numbers to bring his/her produce to the procurement centre in the event of his/her inability to be present in person. In such cases, it should be

ensured that the payment of the produce shall be released to Bank Account of the registered farmer (owner)

- v. Any person can act as an authorized person upto a maximum of three farmers only.
- vi. In case of a leased land, a valid registered lease agreement or State-recognized cultivation proof shall be mandatory. In such cases, the payment shall be released to the registered lessee farmers Bank Account.
- vii. In the case of tenant farmer, an agreement deed between the farmer (owner) and tenant farmer or any other documents recognized by concerned State Government with the proof of cultivation of crop is mandatory. In such cases, the payment shall be released to Bank Account of the registered tenant farmer.
- viii. CNAs/ State (using own portal) must use farmer biometric through Aadhaar enabled POS machine or facial authentication through mobile app in the procurement centers for authentication of genuine farmers before the purchase of produce from them. OTP will not be allowed as a method of authentication. In case of authorized persons also, Aadhaar authentication is mandatory. The Aadhaar authentication is done to ensure only the genuine farmer avails the benefits of the scheme and to keep middlemen away.
- ix. Before the release of the payment to State Level Agencies (SLAs), the CNAs must ensure that all real time data pertaining to PSS operations is fetched in their Portal from State Portal through API integration.
- x. In addition to Primary Coöperative Societies, state agency may also involve Farmers Producers Organization (FPO)/ Farmers Producers Company (FPC) in procurement operations. However, preference must be given to PACS. Each PACS/FPO/FPC can open only one procurement center. The FPO/FPC must be a registered body having an average annual turnover of Rs. 1 crore in the past 3 years. FPO/FPC can take procurement operation only in those village/taluka where its members are present. The registered office of FPO/FPC must be located within the same block/taluka in which the procurement is undertaken from registered farmers. However, it should be ensured that FPO/FPC shall not be allowed to act as State Level Agencies (SLAs) for procurement under PSS.
- xi. The Storage Agencies shall not be engaged to act as a Procuring Agencies & vice-versa in order to avoid the conflict of interest.
- xii. No storage point shall be allowed to open procurement center to ensure smooth deposit of procured stock at the Warehouse.
- xiii. The payment to the registered farmers must be made through Aadhaar Enabled Direct Benefits Transfer (DBT) /Aadhaar verified Bank Account mode only.

B. Market Intervention Scheme (MIS) :

- i. The State/UT must issue a notification under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Service) Act, 2016 by 30th September, 2025 and enclose the same at the time of sending the MIS proposal.
- ii. To get the benefits of the scheme, farmers must be registered in a State portal.
- iii. In the state/UT where Digital Crop Survey(DCS)/integration into Agri Stack is being done, It is mandatory for such State/UT to use farmers details through API integration with DCS/integration into Agri Stack for farmers registration. In case of failure of crop verification using automatically fetched DCS data, verification using traditional crop verification could be undertaken. In states where DCS is not carried out, the traditional crop verification must be adopted.
- iv. The farmer during registration can give name of three authorised persons along with their Aadhaar numbers to bring his/her produce to the procurement centre in the event of his/her inability to be present in person. In such cases, it should be ensured that the payment of the produce shall be released to Bank Account of the registered farmer (owner).
- v. Any person can act as an authorized person upto a maximum of three farmers only.
- vi. In case of a leased land, a valid registered lease agreement or State-recognized cultivation proof shall be mandatory. In such cases, the payment shall be released to the registered lessee farmers Bank Account.
- vii. In the case of tenant farmer, an agreement deed between the farmer (owner) and tenant farmer or any other documents recognized by concerned State Government with the proof of cultivation of crop is mandatory. In such cases, the payment shall be released to Bank Account of the registered tenant farmer.
- viii. Mandatory use of Aadhaar enabled POS-based biometric or facial authentication through mobile app of farmers to ensure the physical presence and identity verification of the farmers at the time of physical procurement. In case of authorized persons also, Aadhaar authentication is mandatory. The Aadhaar authentication is done to ensure only the genuine farmer avail the benefits of the scheme and to keep middlemen away.
- ix. In addition to Primary Cooperative Societies, state agency may also involve Farmers Producers Organization (FPO)/ Farmers Producers Company (FPC) in procurement operations. However, preference must be given to PACS. Each PACS/FPO/FPC can open only one procurement center. The FPO/FPC

must be a registered body having an average annual turnover of Rs. 1 crore in the past 3 years. The FPO/FPC can take procurement operation only in those village/taluka where its members are present. The registered office of FPO/FPC must be located within the same block/taluka in which the procurement is undertaken from registered farmers. However, it should be ensured that FPO/FPC shall not be allowed to act as State Level Agencies (SLAs) for procurement under PSS.

- x. In State/UT where Price Difference Payment (PDP) is opted for implementation, the transaction of trading must take place between the registered farmers and notified traders with farmers biometric through Aadhaar enabled geo-fenced POS machine or facial authentication through mobile app in the notified APMCs having CCTV installation to maintain transparency and accountability. Such CCTV records are required to be kept during the entire implementing period.
 - xi. The payment to registered farmers must be done through Aadhaar enabled Direct Benefit Transfer (DBT)/ Aadhaar verified Bank Account mode only
3. You are, therefore, requested to kindly take due notice of the above instructions for mandatory compliance while preparing the proposal for implementation of PSS & MIS under PM-AASHA. Without the compliance of the above instructions, the proposal of PSS & MIS under PM-AASHA will not be entertained w.e.f Kharif 2025-26 Season.


(Anbalagan P)


Joint Secretary to the Government of India

Copy to :

1. Adviser, Costing Cell, DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Secretaries (Agriculture/Cooperation) of all States and UTs.
3. Managing Director, NAFED, New Delhi.
4. Managing Director, NCCF, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:

PS to AM/ MOS/Sr. PPS to Secretary /Addl. Secretary/AS&FA, (DA&FW)


(Anbalagan P)

Joint Secretary to the Government of India

41-405/12-2-2025

No. L-15016/95/2020-MPS (E-91262)

Government of India

NO. 39992 MS/GI/2025

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Investment & Price Support Division

615/APC/2025

Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated the 11th November, 2025

APC

[Handwritten signature]
11/11/2025
(रवीन्द्र कुमार)

विशेष सचिव एवं सॉफ्ट आफिसर,
TO मुख्य सचिव

Chief Secretaries/UT Administrators of all States/UTs

Subject: Instructions regarding implementation of Price Support Scheme (PSS) and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA.

Madam/Sir,

Please refer to this Department's letter of even no. dated 18th September, 2025 on the subject cited above (Copy enclosed). After careful consideration of the various representations received from States, it has been decided to revise the clause no. x of Para 2 A of above referred letter dated 18th September, 2025 as under:

Para 2 A x.: State agency may also involve Primary Cooperative Societies (PACS), Farmers Producers Organization (FPO)/Farmers Producers Company (FPC) in procurement operations. Each PACS/FPO/FPC can open only one procurement center.

The FPO/FPC must be a registered body with two years in existence having minimum of at least 300 farmer members. FPO/FPC can take procurement operation only in those taluka where its members are present. However, it should be ensured that PACS/FPO/FPC shall not be allowed to act as State Level Agencies (SLAs) for procurement under PSS.

You are, therefore, requested to kindly take due notice of the above changes while preparing the proposal for implementation of PSS under PM-AASHA.

ACS, Horti/PS Agri/PS Cooperative

[Handwritten signature]
(Anbalagan P)
11/11/2025

Joint Secretary to the Government of India

Copy to :

1. Adviser, Costing Cell, DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Secretaries (Agriculture/Horticulture/Cooperation) of all States and UTs.
3. Managing Director, NAFED, New Delhi.
4. Managing Director, NCCF, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:

PS to AM/ MOS/Sr.PPS to Secretary /Addl. Secretary/AS&FA, (DA&FW)

JCC(LBS)

[Handwritten signature]
10/11/2025
सचिव, कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Sr. 2
18.11.25

[Handwritten signature]
(Anbalagan P)
Joint Secretary to the Government of India
18.11.25

No. L-15016/95/2020-MPS (E-91262)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Investment & Price Support Division

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated the 18th September, 2025

To

Chief Secretaries/ UT Administrators of all States/UTs

**Subject : Instructions regarding implementation of Price Support Scheme (PSS)
and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA.**

Madam/Sir,

Please refer to this Department's letter of even no. dated 29th October, 2024 and dated 20th March, 2025 regarding revised guidelines for implementation of Price Support Scheme (PSS), Price Deficit Payment Scheme (PDPS) and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA (Copies enclosed).

2. Apart from the provisions mentioned in the above schemes guidelines, the following instructions are issued for compliance while implementing PSS and MIS under PM-AASHA w.e.f. Kharif 2025-26 Season:

A. Price Support Scheme (PSS) :

- i. The registration of farmers must be done in a Portal devised for farmers registration by Central Nodal Agencies (CNAs) i.e. NAFED and NCCF.
- ii. The states where the registration of farmers is done on State's own Portal must ensure that all data is updated on real time basis and the CNAs should be able to fetch such data daily in their Portal through API integration without which the proposal under PSS will not be entertained.
- iii. **Mandatory Use of Digital Crop Survey/integration into Agri-Stack:** The States/UTs where Digital Crop Survey (DCS) / integration into Agri-Stack is being done, the CNAs /State Governments/UTs/State Level Agencies (SLAs)/Primary Level Agencies (PLAs) must use such data through API integration for auto-verification of farmer registration details. In case of failure of crop verification using automatically fetched DCS data, verification using traditional crop verification should be undertaken. In states where DCS is not carried out, the traditional crop verification must be adopted.
- iv. The farmer during registration can give name of three authorised persons along with their Aadhaar numbers to bring his/her produce to the procurement centre in the event of his/her inability to be present in person. In such cases, it should be

ensured that the payment of the produce shall be released to Bank Account of the registered farmer (owner)

- v. Any person can act as an authorized person upto a maximum of three farmers only.
- vi. In case of a leased land, a valid registered lease agreement or State-recognized cultivation proof shall be mandatory. In such cases, the payment shall be released to the registered lessee farmers Bank Account.
- vii. In the case of tenant farmer, an agreement deed between the farmer (owner) and tenant farmer or any other documents recognized by concerned State Government with the proof of cultivation of crop is mandatory. In such cases, the payment shall be released to Bank Account of the registered tenant farmer.
- viii. CNAs/ State (using own portal) must use farmer biometric through Aadhaar enabled POS machine or facial authentication through mobile app in the procurement centers for authentication of genuine farmers before the purchase of produce from them. OTP will not be allowed as a method of authentication. In case of authorized persons also, Aadhaar authentication is mandatory. The Aadhaar authentication is done to ensure only the genuine farmer avails the benefits of the scheme and to keep middlemen away.
- ix. Before the release of the payment to State Level Agencies (SLAs), the CNAs must ensure that all real time data pertaining to PSS operations is fetched in their Portal from State Portal through API integration.
- x. In addition to Primary Cooperative Societies, state agency may also involve Farmers Producers Organization (FPO)/ Farmers Producers Company (FPC) in procurement operations. However, preference must be given to PACS. Each PACS/FPO/FPC can open only one procurement center. The FPO/FPC must be a registered body having an average annual turnover of Rs. 1 crore in the past 3 years. FPO/FPC can take procurement operation only in those village/taluka where its members are present. The registered office of FPO/FPC must be located within the same block/taluka in which the procurement is undertaken from registered farmers. However, It should be ensured that FPO/FPC shall not be allowed to act as State Level Agencies (SLAs) for procurement under PSS.
- xi. The Storage Agencies shall not be engaged to act as a Procuring Agencies & vice-versa in order to avoid the conflict of interest.
- xii. No storage point shall be allowed to open procurement center to ensure smooth deposit of procured stock at the Warehouse.
- xiii. The payment to the registered farmers must be made through Aadhaar Enabled Direct Benefits Transfer (DBT) /Aadhaar verified Bank Account mode only.

B. Market Intervention Scheme (MIS) :

- i. The State/UT must issue a notification under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Service) Act, 2016 by 30th September, 2025 and enclose the same at the time of sending the MIS proposal.
- ii. To get the benefits of the scheme, farmers must be registered in a State portal.
- iii. In the state/UT where Digital Crop Survey(DCS)/integration into Agri Stack is being done, It is mandatory for such State/UT to use farmers details through API integration with DCS/integration into Agri Stack for farmers registration. In case of failure of crop verification using automatically fetched DCS data, verification using traditional crop verification could be undertaken. In states where DCS is not carried out, the traditional crop verification must be adopted.
- iv. The farmer during registration can give name of three authorised persons along with their Aadhaar numbers to bring his/her produce to the procurement centre in the event of his/her inability to be present in person. In such cases, it should be ensured that the payment of the produce shall be released to Bank Account of the registered farmer (owner).
- v. Any person can act as an authorized person upto a maximum of three farmers only.
- vi. In case of a leased land, a valid registered lease agreement or State-recognized cultivation proof shall be mandatory. In such cases, the payment shall be released to the registered lessee farmers Bank Account.
- vii. In the case of tenant farmer, an agreement deed between the farmer (owner) and tenant farmer or any other documents recognized by concerned State Government with the proof of cultivation of crop is mandatory. In such cases, the payment shall be released to Bank Account of the registered tenant farmer.
- viii. Mandatory use of Aadhaar enabled POS-based biometric or facial authentication through mobile app of farmers to ensure the physical presence and identity verification of the farmers at the time of physical procurement. In case of authorized persons also, Aadhaar authentication is mandatory. The Aadhaar authentication, is done to ensure only the genuine farmer avail the benefits of the scheme and to keep middlemen away.
- ix. In addition to Primary Cooperative Societies, state agency may also involve Farmers Producers Organization (FPO)/ Farmers Producers Company (FPC) in procurement operations. However, preference must be given to PACS. Each PACS/FPO/FPC can open only one procurement center. The FPO/FPC

must be a registered body having an average annual turnover of Rs. 1 crore in the past 3 years. The FPO/FPC can take procurement operation only in those village/taluka where its members are present. The registered office of FPO/FPC must be located within the same block/taluka in which the procurement is undertaken from registered farmers. However, it should be ensured that FPO/FPC shall not be allowed to act as State Level Agencies (SLAs) for procurement under PSS.

- x. In State/UT where Price Difference Payment (PDP) is opted for implementation, the transaction of trading must take place between the registered farmers and notified traders with farmers biometric through Aadhaar enabled geo-fenced POS machine or facial authentication through mobile app in the notified APMCs having CCTV installation to maintain transparency and accountability. Such CCTV records are required to be kept during the entire implementing period.
- xi. The payment to registered farmers must be done through Aadhaar enabled Direct Benefit Transfer (DBT)/ Aadhaar verified Bank Account mode only

3. You are, therefore, requested to kindly take due notice of the above instructions for mandatory compliance while preparing the proposal for implementation of PSS & MIS under PM-AASHA. Without the compliance of the above instructions, the proposal of PSS & MIS under PM-AASHA will not be entertained w.e.f Kharif 2025-26 Season.


(Anbalagan P)


Joint Secretary to the Government of India

Copy to :

1. Adviser, Costing Cell, DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Secretaries (Agriculture/Cooperation) of all States and UTs.
3. Managing Director, NAFED, New Delhi.
4. Managing Director, NCCF, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:

PS to AM/ MOS/Sr. PPS to Secretary /Addl. Secretary/AS&FA, (DA&FW)


(Anbalagan P)

Joint Secretary to the Government of India

Instruction regarding implementation of Price Support Scheme (PSS) and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA.

Binod Giri < b.giri@gov.in >

Tue, 11 Nov 2025 5:56:41 PM +0530

To "cs-andaman"<cs-andaman@nic.in>,"cs"<cs@ap.gov.in>,"cs-arunachal"<cs-arunachal@nic.in>,"cs-assam"<cs-assam@nic.in>,"cs-bihar"<cs-bihar@nic.in>,"csofficecg"<csoffice.cg@gov.in>,"csdelhi"<csdelhi@nic.in>,"cs-goat"<cs-goat@nic.in>,"chiefsecretary"<chiefsecretary@gujarat.gov.in>,"cs"<cs@hry.nic.in>,"cs-hp"<cs-hp@nic.in>,"cs-jandk"<cs-jandk@nic.in>,"cs-jharkhand"<cs-jharkhand@nic.in>,"cs"<cs@karnataka.gov.in>,"chiefsecy"<chiefsecy@kerala.gov.in>,"cs"<cs@mp.nic.in>,"cs"<cs@maharashtra.gov.in>,"cs-manipur"<cs-manipur@nic.in>,"cs-mizoram"<cs-mizoram@nic.in>,"csngl"<csngl@nic.in>,"csori"<csori@nic.in>,"cs-ori"<cs-ori@nic.in>,"cspon"<cs.pon@nic.in>,"cspondicherry"<cs.pondicherry@nic.in>,"cs"<cs@punjab.gov.in>,"csraj"<csraj@rajasthan.gov.in>,"cs-skm"<cs-skm@hub.nic.in>,"cs"<cs@tn.gov.in>,"cs"<cs@telangana.gov.in>,"cs-tripura"<cs-tripura@nic.in>,"csup"<csup@nic.in>,"cs-uttarakhand"<cs-uttarakhand@nic.in>,"chiefsecyuk"<chiefsecyuk@gmail.com>,"cs-westbengal"<cs-westbengal@nic.in>,"agri-meg"<agri-meg@nic.in>

Cc "secagri"<secagri@gujarat.gov.in>,"prs-coop"<prs-coop@karnataka.gov.in>,"acscoop"<acs.coop@maharashtra.gov.in>,"psagriculture"<psagriculture@mp.gov.in>,"agriculturedepartmentaryana"<agriculturedepartmentaryana@gmail.com>,"prsecyagri"<prsecyagri@rajasthan.gov.in>,"psupagri"<psup.agri@gmail.com>,"coopmktgpeshi"<coop.mktgpeshi@gmail.com>,"Poonam"<prlsecy_agr@ap.gov.in>,"apcagrivet"<apcagrivet@gmail.com>,"agridep-bih"<agridep-bih@nic.in>,"acs-agricg"<acs-agri.cg@gov.in>,"secyagrigoa"<secyagri.goa@gov.in>,"agrisecy-hp"<agrisecy-hp@nic.in>,"Jkpsagri"<Jk.psagri@gmail.com>,"jhagriculture"<jhagriculture@gmail.com>,"secretaryagrigoa"<secretaryagrigoa@gmail.com>,"secyagri"<secy.agri@kerala.gov.in>,"agrisec"<agrisec@tn.gov.in>,"vijaymeghalaya2"<vijaymeghalaya2@gmail.com>,"joymongjam"<joymongjam@yahoo.com>,"agrdepimiz2021"<agrdepimiz2021@gmail.com>,"apc-ngl"<apc-ngl@nic.in>,"agrsecor"<agrsec.or@nic.in>,"fcd"<fcd@punjab.gov.in>,"prsecycoop"<prsecy.coop@rajasthan.gov.in>,"yasodha27"<yasodha27@gmail.com>,"bidoltayeng250"<bidoltayeng250@gmail.com>,"secretaryagrigoa"<secretary.agri.got@gmail.com>,"secy-agri"<secy-agri@telangana.gov.in>,"apcofficeup"<apcofficeup@gmail.com>,"secretary"<secretary@ukplanning.in>,"psagri-wb"<ps.agri-wb@nic.in>,"secyps2019"<secy.ps.2019@gmail.com>,"hs-chd"<hs-chd@nic.in>,"fs-dmn-dd"<fs-dmn-dd@nic.in>,"ccfdaman"<ccfdaman@yahoo.com>,"cdevelop"<cdevelop@nic.in>,"secyagrigoa"<secyagri.pon@nic.in>,"agrimin india"<agrimin.india@gov.in>,"agrimin india"<agrimin.india@gmail.com>,"bhagirathchaudhary"<bhagirath.chaudhary@sansad.nic.in>,"Devesh Chaturvedi"<secy-agri@gov.in>,"MANINDER DWIVEDI"<maninder.edu@nic.in>,"Anbalagan P"<anbalagan.p@gov.in>,"Prasenjit Deb"<prasenjit.dob68@gov.in>,"rachnakumar"<rachna.kumar@nic.in>,"Mdccl"<mdcell@nafed-india.com>,"mdnccf"<mdnccf@nccf-india.com>

Respected Madam/Sir

In continuation to this Department letter of even no. dated 18.09.2025 (copy enclosed), please find attached herewith a letter regarding revision in clause no. x of para 2 A of aforesaid letter dated 18.09.2025, for necessary action.

Regards,

—
(Binod Giri)
Deputy Commissioner (MPS),
Investment & Price Support Division,
Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, Room No. 416,
New Delhi-110001
Tel: 23070823

No. L-15016/95/2020-MPS (E-91262)
Government of India **No. 20845 /MS/GI/2026**
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Investment & Price Support Division

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 26th May, 2026

To
Chief Secretaries/ UT Administrators of all States/UTs

Subject: Instructions regarding implementation of Price Support Scheme (PSS) and Market Intervention Scheme (MIS) under PM-AASHA.

Madam/Sir,

Please refer to this Department's communication of even no. dated 18th September, 2025 and dated 11th November, 2025 on the subject cited above (Copy enclosed). Upon careful consideration of the representations received from States and Central Nodal Agencies (CNAs), it has been decided to revise Clause (iii) of Para 2 (A) of aforementioned communication dated 18th September, 2025 as under:

3. In States and UTs where development of Farmer Registry/Digital Crop Survey under the AgriStack initiative is under progress, the CNA/SLA/PLA - to use such digitally integrated data for farmers and crops of registered farmers. However, the States/UTs shall ensure that no genuine farmer is denied benefits and may enroll such farmers through exception mechanisms in cases where they do not have Farmer ID. Any technical issue faced in digital verification should not adversely impact the procurement process. It shall be the responsibility of the States and UTs to ensure that crop verification of registered farmers is completed well in time through digital or manual survey to enable timely procurement of crops and payment to farmers. The States/UTs may pursue with the farmers registered through the exception mechanism so that they obtain Farmer ID by the next procurement season.

4. You are, therefore, requested to kindly take due notice of the above changes while preparing the proposal for implementation of PSS under PM-AASHA.

Encl. as above,

Joint Secretary to the Government of India

Copy to:

- 1. Adviser, Costing Cell, DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
- 2. Secretaries (Agriculture/Horticulture/Cooperation/Marketing) of all States and UTs.
- 3. Managing Director, NAFED, New Delhi.
- 4. Managing Director, NCCF, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:

PS to AM/ MOS/Sr.PPS to Secretary /Addl. Secretary/AS&FA, (DA&FW)

श्रीशिवम
01/6/25

Joint Secretary to the Government of India